CMYK

प्रभात खबर

पटना,सोमवार, 4 अक्तूबर, 2010

मेरे सपनों का बिहार

मुसलिम वोट बैंक पर है सबकी नजर

बिहार में परिसीमन के बाद 100 विधानसभा क्षेत्रों में मुसलिम मतदाताओं की अच्छी-खासी संख्या है. विधानसभा चुनाव में राजद को यदि असरदार उपस्थिति दर्ज करानी है, तो उसे अपने मुसलिम वोट बैंक को बिखरने से बचाना होगा. दूसरी ओर जद(यू)-भाजपा गठबंधन को यदि अपने पिछले प्रदर्शन को सुधारना है, तो उसे मुसलिम वोट बैंक में सेंध लगानी ही होगी. इन दोनों के बीच कांग्रेस भी अच्छी सफलता की उम्मीद तभी कर सकती है, जब वह बड़ी संख्या में मुसलिम मतों को लुभाने में कामयाब होती है. राज्य में मुसलिम मतों को लुभाने-मनाने का दिलचस्प खेल जारी है, जिसके नतीजे के लिए चुनाव तक का इंतजार तो करना ही होगा.

संजय कुमार

बिहार में चुनावी अखाड़ा सजते ही सभी प्रमुख पार्टियां मुसलिम मतदाताओं को रिझाने के उपाय में जुट गयी हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहां कभी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के अत्यंत विश्वासपात्र रहे तसलीमुद्दीन को अपने पाले में खींचने में कामयाब रहे हैं, वहीं लालू इस समय सीवान जेल में हत्या के आरोप में बंद सहाबुद्दीन को मनाने के लिये पूरा जोर लगा रहे हैं. सहाबुद्दीन न केवल सीवान संसदीय क्षेत्र से चार बार सांसद रहे हैं, बल्कि खासकर सीवान और आसपास के जिलों के मुसलिम मतदाताओं को राजद के पक्ष में करने में भी सफल रहे हैं. यदि किशनगंज और आसपास के जिलों के मुसलिम मतदाताओं पर तसलीमुद्दीन की अच्छी पकड मानी जाती है, तो उत्तर पश्चिमी बिहार में राजद के लिये यही भूमिका सहाबुद्दीन निभाते रहे हैं. मुसलिम मतदाताओं को रिझाने के इस दौड़ में कांग्रेस भी पीछे नहीं रहना चाहती. हालांकि पार्टी ने दूसरे दलों के मुसलिम नेताओं को अपने पाले में खींचने का प्रयास न कर अपने नेता चौधरी महबूब अली कैसर को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी सौंपी है. इस विश्वास के साथ कि पार्टी का मुसलिम नेतृत्व मुसलिम मतों को आकर्षित करने में कामयाब होगा.

सहाबुद्दीन और तसलीमुद्दीन भले ही मुसलिम मतों पर मजबूत पकड़ रखने वाले नेता माने जाते हों, लेकिन दोनों की अपनी सीमाएं हैं. बिहार के मुसलमान नीतीश सरकार के पिछले पांच साल के कामों से भले ही खुश हों, लेकिन भाजपा के साथ गठबंधन होने के कारण उनका जद (यू) के पक्ष में मतदान करना आसान नहीं दिखता. ऐसे में सवाल यह उठता है कि जद (यू) में शामिल हुए मुसलिम नेता तसलीमुद्दीन क्या मुसलमानों का मत भी जद (यू) को दिलवा पायेंगे? या फिर जद (यू) के राज्यसभा सांसद अली अनवर मुसलमानों को रिझाने में सफल हो पायेंगे?

यह सही हो सकता है कि सहाबुद्दीन पिछले चुनावों में बड़ी संख्या में मुसलिम मतों को लालू के पक्ष में लाने में कामयाब रहे हैं. लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि उस दौर में लालू प्रसाद एक ऐसे नेता के रूप में उभरे थे, जिनके बारे में माना जाता था कि मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने पर वे बिहार में बड़ा बदलाव ला सकते हैं, मुसलमानों को सुरक्षा दिला सकते हैं, दलितों एवं गरीबों को उनका आत्म सम्मान लौटा सकते हैं और अन्य पिछड़े वर्गों को राजनीतिक शक्ति प्रदान कर सकते हैं. हो सकता है इनमें से कुछ अपेक्षाओं पर वे खड़े भी उतरे हों, लेकिन अत्यंत बदतर सत्ता

संचालन, राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने, अपराध एवं भ्रष्टाचार बढ़ने के कारण राज्य के बड़े तबके का मोह उनसे पूरी तरह भंग हो गया. मुसलमानों को लालू के लंबे राज में भले ही सुरक्षा का अहसास हुआ हो, लेकिन वे भी अब आगे बढ़ना चाहते हैं, विकास की इच्छा रखते हैं.

लालू पिछले पांच साल से सत्ता से दूर हैं. इस दौरान भाजपा के साथ गठबंधन के बावजूद जद (यू) सरकार के शासन से मुसलमानों को किसी तरह के खतरे का अहसास नहीं हुआ. लालू ने जहां इस अवधि में मुसलमानों

को लुभाने वाला कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया, वहीं नीतीश सरकार ने कोई ऐसा नकारात्मक काम नहीं किया जिससे मुसलमान नाराज हों. ऐसे में यह सवाल उठना वाजिब है कि सहाबुद्दीन यदि मान भी गए तो मुसलमानों को राजद के पक्ष में मतदान के लिए मनाने में कामयाब हो पायेंगे? सहाबुद्दीन के लिए इस बार रास्ते आसान नहीं हैं. मुसलमानों के बीच अब उनका पहले जैसा प्रभाव नहीं रह गया है. यह बात 2009 के लोकसभा चुनाव में सीवान संसदीय क्षेत्र से राजद उम्मीदवार के रूप में उनकी पत्नी हिना सहाब के चुनाव हारने से साबित हो चुकी है.

आखिर ऐसा क्या है कि राजनीतिक पार्टियां बिहार में मुसलिम मतों को लेकर इतनी बेताब दिख रही हैं? इस सवाल का जवाब देना कठिन नहीं है. 2001 की जनगणना के मुताबिक बिहार में कुल आबादी का 16.5 फीसदी मुसलमान हैं. संख्या बल के हिसाब से देखें तो वे यादवों (करीब 17.5 फीसदी) से थोड़ा ही कम हैं. यदि हम विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के जातीय एवं सामुदायिक समीकरणों पर नजर डालें तो तसवीर थोड़ी अलग नजर आती है. मुसलमानों की आबादी कुछ खास जिलों में केंद्रित है, जहां वे अन्य जातियों की तुलना में अधिक निर्णायक भूमिका निभाते हैं.

परिसीमन के बाद 243 विधानसभा क्षेत्रों में से 100 में मुसलिम मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है. इन क्षेत्रों में मुसलमानों की आबादी भले ही अलग-अलग (15 से 75 फीसदी के बीच) हो, लेकिन खास बात यह है कि यहां वे चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की स्थिति में हैं. इनमें से दस विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं, जहां मुसलिम मतदाता बहुमत में (50 फीसदी या उससे अधिक) हैं. दस अन्य क्षेत्रों में कुल मतदाताओं का एक तिहाई से अधिक (33 से 49 फीसदी) मुसलिम हैं. 20 अन्य क्षेत्रों में मुसलिम मतदाता 25 से 32 फीसदी हैं. इस तरह कुल 40 विधानसभा क्षेत्रों में मुसलिम मतदाता एक चौथाई से अधिक हैं. अन्य 60 विधानसभा क्षेत्रों में मुसलिम मतदाताओं की संख्या कुल मतदाताओं का 15 से 24 फीसदी है.

आमतौर पर देखा जाता है कि मुसलिम समुदाय के ज्यादातर मतदाता एकतरफा मतदान करते हैं, खासकर किसी एक राजनीतिक दल के पक्ष में. हालांकि कुछ क्षेत्रों में कई मुसलिम उम्मीदवारों के होने पर इस चलन में थोड़ा अंतर हो जाता है. यह तथ्य बिहार के मुसलिम मतदाताओं पर ही लागू नहीं होता, देश के दूसरे राज्यों में भी करीब-करीब ऐसी ही स्थिति है. यही कारण है कि मुसलमानों को एक निर्णायक वोट बैंक के रूप में देखा जाता है और सभी पार्टियां इसे अपने पाले में करने की पुरजोर कोशिश करती हैं. चुनाव की घोषणा के साथ ही बिहार की प्रमुख पार्टियां भी ऐसी ही कोशिश में जुट गयी हैं. बिहार में पिछले कुछ चुनावों के दौरान सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज (सीएसडीएस), दिल्ली की ओर से कराये गये विभिन्न सर्वे से पता चलता है कि राज्य के ज्यादातर मुसलिम मतदाता राजद को अपना मत देते रहे हैं. सर्वे के आंकडों के मुताबिक 1996 के लोकसभा चुनावों में राज्य के 61 फीसदी मुसलिम मतदाताओं ने राजद (तब जनता दल) के पक्ष में मतदान किया. 1998 और 99 के लोकसभा चुनावों के दौरान मुसलिम मतों का राजद के पक्ष में और अधिक ध्रुवीकरण (क्रमश: 68 और 77 फीसदी) हुआ. 2004 के लोकसभा चुनावों से पहले राजद का अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन होने के कारण उस चुनाव में मुसलिम मतदाता पूरी तरह राजद के पक्ष में खड़े दिखे. हालांकि अगले साल हुए विधानसभा चुनावों में राजद के पक्ष में यह ध्रुवीकरण कुछ कम हुआ, फिर भी मुसलिम मतदाताओं का बहुमत राजद के पक्ष में ही दिखा. लेकिन 2009 का लोकसभा चुनाव आते-आते राजद से मुसलमानों का मोह भंग हो चुका था. उस चुनाव

में सिर्फ 30 फीसदी मुसलमानों ने राजद के पक्ष में मतदान किया. बिहार में 2009 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने वाली कांग्रेस ने राजद के मुसलिम वोट बैंक में बड़ी सेंध लगायी. हालांकि नीतीश कुमार ने भी मुसलिम मतों को रिझाने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन वे जद (यू)- भाजपा गठबंधन के प्रति मुसलमानों में खास रुझान पैदा नहीं कर सके. मुसलिम मतदाताओं को लुभाने की जोर-आजमाइश आज भी जारी है. सहाबुद्दीन के साथ लालू की मीटिंग को इसी दिशा में एक प्रयास के रूप में देखा जाना चाहिए. उधर, नीतीश सरकार ने मुसलमानों के हित में कई काम किये हैं. इनमें 2400 और मदरसों को मान्यता का वादा, अल्पसंख्यकों के छात्रावासों के लिए अनुदान, पुलिस में अल्पसंख्यक युवाओं की बहाली के लिए उन्हें विशेष प्रशिक्षण देना, मुसलिम अनाथालयों के लिए सहायता आदि शामिल हैं. लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इन कामों के दम पर मुसलिम मतदाता इस बात की अनदेखी कर पायेंगे कि जद (यू) का भाजपा के साथ गठबंधन है. कुल मिलाकर इस विधानसभा चुनाव में राजद को यदि अपनी असरदार उपस्थिति दर्ज करानी है तो उसे अपने मुसलिम वोट बैंक को बिखरने से बचाना होगा. सर्वविदित है कि राजद की पिछली सफलताओं में एम-वाई (मुसलिम-यादव) समीकरण की ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है. दूसरी ओर जद (यू)-भाजपा गठबंधन को यदि अपने पिछले प्रदर्शन (143 सीट) को सुधारना है तो उसे मुसलिम वोट बैंक में सेंध लगानी ही होगी. इन दोनों के बीच कांग्रेस भी बिहार में अच्छी सफलता की उम्मीद तभी कर सकती है जब वह बड़ी संख्या में मुसलिम मतों को लुभाने में कामयाब होती है. राज्य में मुसलिम मतों को लुभाने-मनाने का दिलचस्प खेल जारी है, जिसके नतीजे के लिए चुनाव तक का इंतजार तो करना ही होगा.

(लेखक सीएसडीएस, दिल्ली में फेलो और वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं)

आधारभूत संरचना के विकास पर हो जोर

एन के सिंह
टीवी पत्रकार

आज जब हम नीतीश की बात करते हैं. तो हमें सबसे पहले ज्ञात होनी चाहिए कि किसी भी विकास प्रक्रिया में दो हिस्सा होता है. प्रत्यक्ष डिलीवरी और अप्रत्यक्ष डिलीवरी. अप्रत्यक्ष डिलीवरी में सरकार आधारभूत संरचना पर ध्यान देती है. बड़े-बड़े बांध, सिंचाई परियोजना बनाती है. जबकि प्रत्यक्ष डिलीवरी के अंतर्गत सरकार अल्पकालिक लाभ से संबंधित कार्यक्रम एवं योजनायें जनता के लिए लेकर आती है. आज प्रत्यक्ष डिलीवरी के सर्वश्रेष्ठ प्रयोगकर्ताओं की श्रेणी में नीतीश कुमार का भी नाम शामिल है. इसमें यह होता है कि अगर आपकी बेटी जो पांचवी कक्षा में पढ़ रही है तो सरकार आपकी बेटी को साईकिल देगी. जब गांवों में बच्ची साइकिल से स्कूल जाती है तो घर से स्कूल के बीच जब कोई भी आदमी उसे देखता है तो यह जरूर कहता है कि राज्य ने उसे यह साईकिल उपलब्ध कराया है. इसका राजनीतिक फायदा होता है. प्रदेश के कानून व्यवस्था पहले से बेहतर है. लेकिन अभी बहुत कुछ करना शेष है. क्योंकि अभी भी बिहार में बाहर से

निवेश नहीं हो रहा है. एक चीज तो आज बिहार में देखने को मिल रही है, वह है लोगों के बीच सामूहिक चेतना का उभार. यह उत्साहवर्धक है. हाल ही में आंगन बाड़ी में काम करने वाली एक महिला से जब किसी अफसर ने घूस मांगा तो महिला ने अपने पति और गांव के लोगों के मिलकर अफसर की खैर ली. इस सामूहिक सकारात्मक दबाव को एक कुशल राजनैतिक नेतृत्व चाहिए जो उसे उचित दिशा प्रदान कर सके. तब बिहार शायद सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में सबसे तेजी से उभरता राज्य होगा. पंचायत राज में आरक्षण देने से महिलाओं में सशक्तिकरण आयेगा. परंतु इस बात का भय तो बना रहेगा कि उसका पति पिछ्ली सीट से हुकूमत ना चलाये. जब तक सबसे पहले उसे शिक्षा नहीं देंगे. लोकतांत्रिक प्रणाली से बावस्ता नहीं करेंगे. तब तक उसके अर्थपूर्ण परिणाम नहीं आयेंगे.बिहार के लिए सबसे पहत्वपूर्ण बात यह है कि यहां चुनाव बाढ़ के मुद्दे पर नहीं होते, कोई सरकार से यह नहीं पूछ्ता की आपकी बाढ़ नियंत्रण की नीति क्या है? आपने कितने किसानों को किस दर पर बीज दिये. यहां लोग चुनाव इस बात पर चुनाव लोग लड़ते हैं कि वहां अपने जाति का उम्मीवार है की नहीं. बिहार में कृषि विकास की रीढ़ होनी चाहिए. राज्य की 80 प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर है. आने वाली सरकार को कृषि उत्पादन पर ध्यान देना चाहिए.

मैं लौटना चाहता हूं

मजबूरी में माटी से दूर

ओम प्रकाश सिंह
ग्राम - पिपरा बंगला
जिला: अरवल, बिहार
उम्र : 28
छह साल से नोएडा में

'मेरी मिट्टी मुझे बहुत प्यारी है मगर मजबूरी इस अहसास पर भारी पड़ जाती है. पेट की आग बुझाने के लिए मैंने तो सिर्फ अपना राज्य ही छोड़ा है, वरना लोग तो दूसरे देशों में भी काम करने के लिए तैयार रहते हैं. अगर बिहार सरकार मुझे नौकरी दे तो मैं अभी इसी वक्त बिहार लौटने के लिए तैयार हूं.' यह कहना है बिहार के अरवल जिले के पिपरा बंगला गांव के ओमप्रकाश सिंह का.

ओमप्रकाश 6 सालों से नोएडा की एक एक्सपोर्ट कंपनी में काम कर रहे हैं. महज 5 हजार की पगार पर अपने दो बच्चों और पत्नी को साथ घर से दूर रह रहे ओमप्रकाश का दर्द समझना आसान नहीं है. ये वही समझ सकता है जिसने पलायन का दंश झेला हो. बिहार में उनकी थोड़ी सी खेती भी है जिस पर उनके बाकी घर वाले खेती करते हैं. अल्प शिक्षा के कारण उन्हें बिहार में नौकरी नहीं मिली. वहां जो भी काम करते थे उसका पूरा-पूरा मेहनताना नहीं मिल पाने की वजह से वे बिहार को छोड़कर पराये राज्य में काम करने चले आये. ओम प्रकाश कहते हैं कि जो खर्च हम किराया-भाड़ा में करते हैं, अगर हमको वहीं काम मिलता तो यह खर्च हमारी एक बचत होती. विकास की बात पर ओम प्रकाश कहते हैं कि सड़कें तो बनी हैं, स्कूल तो बने हैं, लेकिन अभी तक औद्योगिक विकास के तहत कंपनियों की कमी के चलते वहां रोजगार की संभावनाएं कम हैं. यही कारण है कि जो लोग बाहर रह कर काम कर रहे हैं वो बिना निश्चितता के वापस नहीं जाना चाहते. बिहार चुनाव पर ओमप्रकाश कहते हैं कि नीतीश जी का यह संकल्प कि आने वाले 5-7 वर्षों में वो सभी बिहारियों को वापस बिहार बुला लेंगे और नौकरी भी देंगे, इसमें सच्चाई नजर आती है.

बिहार पोस्ट कार्ड

बिहार को देने की बारी

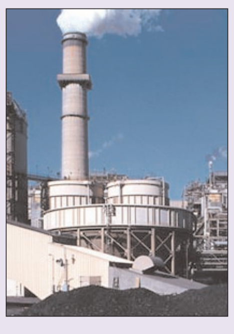

बिहार में कुछ हद तक परिवर्तन की हवा बहती हुई महसूस हो रही है. बच्चे विद्यालय जाना चाहते हैं. लोगों में शिक्षा के अभाव का ज्ञान हो रहा है. बहुत सारे एनजीओ इन चीजों को ध्यान में रख रही है. अगर केंद्र बिहार में औद्योगिक विकास के लिए वचनबद्ध हो जाये तो, सर्वांगीण विकास स्वत: ही हो जायेगा. इतना ही नहीं लोगों को उनके स्वयं के कर्त्तव्य का भी ज्ञान होने लगेगा. मेरा यह मानना है, कि आज तक मैंने समाज से तो लिया ही है, अब देने की बारी है. शायद यही बिहार में विकास की नदी को निरंतर चलायमान कर सकती है.

- पंकज ठाकुर, पटना, बिहार

(जल्द आने वाली पुस्तक 'सुशासन के आईने में नया बिहार' से)

आंकड़ों का आईना

बिहार के चुनावों में जनता दल/राजद को मुसलिम मतों का घटता-बढ़ता समर्थन

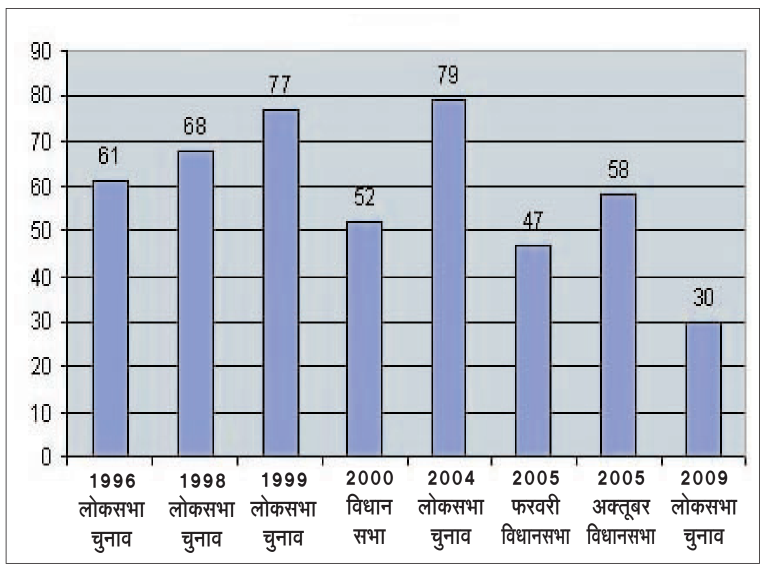

वे विधानसभा क्षेत्र जहां परिसीमन के बाद 50 फीसदी से अधिक मुसलिम मतदाता हैं-

अमोर, कोचधमन, बैसी, बहादुरगंज, जोकीहाट , बलरामपुर, किशनगंज, ठाकुरगंज, अररिया, प्राणपुर

वे विधानसभा क्षेत्र जहां 25 से 49 फीसदी मुसलिम मतदाता हैं-

कस्बा, कादवा, मनिहारी, फारबिसगंज, बिस्फी, ढाका, कोरहा, बाजपती, केओती, सिकती, जाले, बरारी, सिकता, भागलपुर, नरकटियागंज, पूर्णिया, परिहार, सिवान, नरकटिया, कटिहार, रानीगंज (एससी), दरभंगा, बेतिहा, बरहरिया, नरपतगंज, दरभंगा ग्रामीण, गया टाउन, सुगौली, रघुनाथ पुर, बिहार शरीफ

वे विधानसभा क्षेत्र जहां 15 से 24 फीसदी मुसलिम मतदाता हैं-

मधुबनी, नाथनागर, सुरसंड, बरौली, गोपालगंज, छातापुर, रक्सौल, अलीनगर, गौरा बौरम, रामनगर (एससी), चनपतिया, लौरिया, कांती, धमदाहा, कहलगांव, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, हथुआ, हरसिद्धि (एससी), समस्तीपुर, गोरियाकोठी, बेनीपट्टी, नौतन, दुरैया (एससी), साकरा (एससी), औराई, सुपौल, साहेबपुर कमाल, हयाघाट, बेलागंज, तेगहरा, पिपरा, सिमरी बख्तियारपुर, महिशी, शिओहार, कुरहनी, पतेपुर (एससी), रीगा, बगहा, रूनीसईदपुर, हारलाखी, महुआ, निर्मली, सासाराम, चिरइया, लौकहा, कुचईकोट, गोविंदगंज, केसरिया, बारूराज, बहादुरगंज, राजनगर (एससी), पटना साहिब, इमामगंज (एससी), झंझरपुर, बेनीपुर, मरहौरा, बेगूसराय

बिहार @ साइबर वर्ल्ड

दो पाटन के बीच

■ **पीयूष पांडे**

ब्लॉगिंग की दुनिया अनूठी है. लेकिन, ब्लॉगिंग का महत्व सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि इसके जरिए हर शख्स लेखक है. इसकी अहमियत इसलिए भी है क्योंकि ब्लॉगिंग के जरिए कई बार आम लेखक की दृष्टि उन असामान्य बातों पर चली जाती हैं, जो अमूमन दिखायी नहीं देतीं. कई ऐसी खबरों पर ब्लॉगर अपनी बात कहता है, जो तेजी से आती खबरों के बीच छिटकी पड़ी होती हैं. मीडिया से जुड़े रंजीत का ब्लॉग 'दो पाटन के बीच' भी ऐसा ही ब्लॉग है. हालांकि, ब्लॉग का पता यानी यूआरएल है-'कोशीमानी डॉट ब्लॉगस्पॉट डॉट कॉम'.

... किसी बात की कमी नहीं है. टका है, गाड़ी है, अच्छी चुनावी जाति में जन्म लिए हैं, नारे लगाने के लिए चमचे हैं, गोली चलाने के लिए गुंडे हैं, तो विधायक का चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते?

इस ब्लॉग पर कई पोस्ट हैं, जो विविध विषयों से जुडी हैं, लेकिन इन दिनों बिहार चुनाव को लेकर भी यहां कुछ दिलचस्प पोस्ट हैं. मसलन बिहार में टिकट की मारामारी पर वे 'टिकट दीजिए, हमहूं लड़ेंगे चुनाव' व्यंग्य में शानदार तरीके से इस गंभीर होती बीमारी पर चोट करते हैं. लिखते हैं- मुखिया को टिकट चाहिए, वार्ड मेंबर को टिकट चाहिए. प्रखंड समिति के मेंबरों को टिकट चाहिए और जिला परिषद वाले को तो चाहिए ही चाहिए. दुखू को भी चाहिए और सुखू को भी चाहिए. यादव जी को चाहिए, महतो जी को चाहिए. पासवान जी को चाहिए तो राम जी को क्यों नहीं चाहिए. किसी बात की कमी नहीं है. टका है, गाड़ी है, अच्छी चुनावी जाति में जन्म लिए हैं, नारे लगाने के लिए चमचे हैं, गोली चलाने के लिए गुंडे हैं, तो विधायक का चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते?

ब्लॉग के जरिये जानकारी मिलती है कि कालजयी साहित्यकार फणीश्वरनाथ रेणु के बड़े बेटे पद्मपराग को भारतीय जनता पार्टी ने फारबिसगंज सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है. फिर इस सूचना का बारीकी से विश्लेषण किया गया है. निश्चित रूप से ब्लॉग बिहार केंद्रित नहीं है, लेकिन कई पोस्ट खास हैं. बिहार चुनाव के दौरान संभव है और पोस्ट यहां दिखें.

मारम् च धाड़म

कउन किसके साथ है जी

■ **आलोक पुराणिक**

सीबीआई के छापे बहुत बुरे होते हैं जी, अपने भी साथ छोड़ जाते हैं. हम सिर्फ लालूजी की बात नहीं ना कर रहे हैं. रिश्तेदार छोड़कर दूसरी दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं. बिहार का सिचुएशन समझना आसान नहीं है, और उसे समझाना तो और भी डिफिकल्ट है जी. एक छात्र से बिहार का पालिटिक्स पर यह चर्चा हुआ- सरजी यह बताइए कि बिहार में कउन किसके साथ है जी.

देखिये, रामविलास पासवानजी यूं तो लालूजी के साथ हैं, पर नहीं भी हैं. लालूजी यूं तो कांग्रेस के साथ हैं, पर कांग्रेस उनके साथ नहीं है. ऐसे ही जेडी(यू) भाजपा के साथ है, पर वह भाजपा के वरुण गांधी और नरेंद्र मोदी के साथ नहीं हैं. मतलब जेडी (यू) वाले जब भी स्टेटमेंट इशु करते हैं, तो क्लेरिफाई करते हैं कि हम साथ-साथ हैं, पर इसका मतलब नहीं कि हम वरुण गांधी या नरेंद्र मोदी के साथ हैं. मतलब साथ-साथ भी हैं और साथ-साथ नहीं भी हैं -मैंने समझाने की कोशिश की. ये क्या बात हुई कि साथ-साथ भी हैं और साथ-साथ नहीं भी हैं -स्टूडेंट डांट रहा है. भई पालिटिक्स में यही है कि जो होता है, वह नहीं भी होता है. अब जैसे नेता कहता है कि वह बहुतै गरीब है, पर वह नहीं होता है -मैंने समझाने की कोशिश की. अजी नेता है, तो गरीब काहे होगा जी. गरीबी रेखा नेताओं से तो बचकर चलती है ना -छात्र ने पूछा.

... भई पालिटिक्स में यही है कि जो होता है, वह नहीं भी होता है. अब जैसे नेता कहता है कि वह बहुतै गरीब है, पर वह नहीं होता है. अजी नेता है, तो गरीब काहे होगा जी...

बेटा, जैसे मलाइका अरोड़ा पहचान में तब ही आती है, जब वह मुन्नी बदनाम हुई का गीत गाती है, वैसे ही नेता पहचान में तब ही आता है, जब वह गरीबी टाइप की बात करता है. पर सच्ची का गरीब हो लिया नेता, तो फिर संकट हो जाता है. पब्लिक इस डर से वोट नहीं देती कि ये अपनी ही गरीबी दूर ना कर पा रहे, हमारी गरीबी क्या दूर करेंगे -मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की. आप बता रहे थे कि पासवानजी लालूजी के साथ हैं, पर नहीं भी हैं -छात्र ने फिर पूछा. देखिये पासवानजी एक जमाने में भाजपा के साथ थे, फिर भाजपा की एंटी पार्टी की सरकार में मंत्री भी हो लिये. कई सालों तक कुरसी के पास रहे, आजकल नहीं हैं, तो उन्हें पहचानना मुश्किल होता है कि किसके साथ हैं. वैसे वह लालूजी के साथ हैं, पर यूं नहीं भी हैं-मैंने फिर समझाने की कोशिश की. यह क्या बात हुई कि हैं भी और नहीं भी. सरजी आप तो कनफ्यूजन मचा रहे हैं. बिहार का पालिटिक्स से शुरू हुए थे, कनफ्यूजन पर खत्म हुए हैं -स्टूडेंट कह रहा है. हां बेटा, अगर हम कनफ्यूजन से शुरू होंगे, तो बिहार का पालिटिक्स पर पहुंच जायेंगे. नहीं क्या?

राष्ट्रीय फलक

मोदी वरुण आउट, नत्था इन

■ **कमलेश कुमार सिंह**

क्या गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और वरुण गांधी बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रचार अभियान में शामिल होंगे? यह सवाल पिछले कई दिनों से सियासी गलियारे में तैर रहा था. अब इस सवाल का जवाब आ चुका है. *द इंडियन एक्सप्रेस* ने इसी मसले को लेकर एक खबर छापी है. खबर के अनुसार, मोदी और वरुण गांधी बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान में शामिल नहीं होंगे.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी अल्पसंख्यक परक छवि को कायम रखने के लिए इन दोनों नेताओं को प्रचार अभियान से दूर रखने की बात लंबे अरसे से करते आ रहे थे. भाजपा द्वारा चुनाव आयोग को प्रचार अभियान में शामिल किये जाने वाले नेताओं की सूची में मोदी और वरुण का नाम शामिल नहीं है. इस मसले पर पार्टी खुद को घिरने से बचाने के लिए इस सूची में किसी भी मुख्यमंत्री का नाम शुमार नहीं किया है. इस बार भाजपा-जदयू गंठबंधन बिहार विधानसभा चुनाव में विकास और सुशासन को मुख्य मुद्दा बना रहा है. लेकिन भाजपा के विकास और सुशासन को चेहरा माने जाने वाले मोदी को इससे दूर रखने पर विवश होना पड़ा.

पीपली लाइव के नथ्था बिहार चुनाव के दौरान ही मतदाताओं को जागरूक करते नजर आयेंगे. हालांकि यह जागरूकता अभियान मतदान को लेकर नहीं एक खास मकसद से चल रहा है...

पीपली लाइव के नथ्था का नाम आजे बच्चे-बच्चे के जुबान पर है. नथ्था अब बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान ही मतदाताओं को जागरूक करते नजर आयेंगे. हालांकि यह जागरूकता अभियान मतदान को लेकर नहीं बल्कि एक खास मकसद से चलाया जा रहा है. *द टाइम्स ऑफ इंडिया* की एक खबर के अनुसार, पीपली लाइव का यह हीरो ग्रीनपीस संस्था द्वारा चलाये जाने वाले एक जागरूकता अभियान में शामिल होगा. पर्यावरण बचाव अभियान चलाने वाली अग्रणी संस्था ग्रीनपीस अक्षय ऊर्जा के विकेंद्रीकरण के क्षेत्र में बिहार को रोल मॉड्ल बनाना चाहती है. फिल्म में नथ्था बने ओंकार दास मानिकपुरी आरा के एक थियेटर ग्रुप के साथ नुक्कड़ नाटक का भी मंचन करेंगे.